

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-41
25 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

कार्बन ट्रेडिंग मार्केट

*41. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पारिस्थितिकीय रूप से सतत् परिपाटियों में शीघ्र अभिवृद्धि करने के लिए कार्बन क्रेडिट के विधिमान्यकरण और सत्यापन की अधिक सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) अगले पांच वर्षों के दौरान कार्बन ट्रेडिंग मार्केट का भावी अनुमान क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"कार्बन ट्रेडिंग मार्केट" के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.07.2024 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार ने जून, 2023 में कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने प्रत्यायित कार्बन सत्यापन एजेंसियों के लिए प्रत्यायन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड प्रकाशित किए हैं। बीईई ने अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी प्रकाशित की है जिसमें कार्बन क्रेडिट का प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। कथित प्रक्रियाएं व्यापक तौर पर वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

सीसीटीएस में दो व्यवस्थाएं नामतः अनुपालन व्यवस्था/और ऑफसेट व्यवस्था शामिल हैं। अनुपालन व्यवस्था एक अनिवार्य स्कीम है जहां ऊर्जा गहन क्षेत्रों के उद्योगों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) प्रबलता (टी सीओ 2/टी) लक्ष्य दिए जाएंगे और लक्ष्यों की तुलना में निष्पादन के आधार पर, उद्योगों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे या ये उन्हें खरीदने होंगे।

ऑफसेट व्यवस्था एक स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कंपनियां पारिस्थितिक रूप से सतत प्रणालियों सहित अपनी जीएचजी शमन परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं। ऐसी परियोजनाएं जीएचजी उत्सर्जन में कमी के प्रमाणीकरण और सत्यापन पर आधारित कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

(ग) : अगले पांच वर्षों में भारतीय कार्बन बाजार की वृद्धि विकसित विनियामक फ्रेमवर्क, कार्बन क्रेडिट चाहने वाली कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं, प्रौद्योगिकी उपलब्धता और कंपनियों की निवेश क्षमताओं सहित कई प्रमुख कारकों पर निर्भर होगी।
